शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 51 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 51 अंक – 37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 7 – 14 सितम्बर 2026 मूल्य पांच रूपये

शिमला जिला परिषद हार से कांग्रेस में खलबली

दिल्ली में मंत्रियों की सक्रियता के बीच हाईकमान के सामने बढ़े सवाल

शिमला/शैल। शिमला जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा की जीत ने कांग्रेस के लिये बड़ा राजनीतिक झटका दिया है। 25 सदस्यीय जिला परिषद में भाजपा समर्थित 11, कांग्रेस समर्थित 10 और चार निर्दलीय सदस्य थे। इसके बावजूद भाजपा अपने उम्मीदवारों को दोनों प्रमुख पदों पर बैठाने में सफल रही। करीब 26 साल बाद जिला परिषद की कमान कांग्रेस के हाथ से निकलना शिमला में पार्टी के संगठनात्मक प्रभाव के लिए गंभीर संकेत माना जा रहा है।

इस हार की अहमियत इसलिये बढ़ जाती है क्योंकि शिमला जिले से कांग्रेस के चार विधायक और सरकार में तीन मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू भी चुनावी घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थे। इसके बावजूद पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में पर्याप्त समर्थन नहीं जुटा सकी। भाजपा की रणनीति में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन और सांसद डॉ. सिकंदर कुमार की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चुनाव लंबे समय से लंबित था और इसके लिए कांग्रेस के पास तैयारी का पर्याप्त समय था। ऐसे में परिणाम ने पार्टी के भीतर संगठनात्मक तालमेल और स्थानीय स्तर पर प्रभावी रणनीति को लेकर सवाल खड़े कर दिये हैं। भाजपा ने सीमित संख्या होने के बावजूद निर्दलीय सदस्यों का समर्थन जुटाकर बाजी पलट दी।

इसी बीच पिछले दिनों दिल्ली में मंत्रियों की सक्रियता ने प्रदेश कांग्रेस के भीतर चल रही चर्चाओं को और हवा दी। कई मंत्रियों के हाईकमान के नेताओं से मिलने और प्रदेश के राजनीतिक तथा सरकारी कामकाज से जुड़े मुद्दे रखने की खबरें सामने आयी है। हालांकि इन बैठकों के बाद किसी बड़े फैसले की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मंत्रियों का दिल्ली जाकर अपनी बात रखना पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सामने जरूर लाता है।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की सीबीएसई स्कूलों को लेकर सामने आई राय भी इसी संदर्भ में चर्चा में है। उन्होंने पुराने सरकारी स्कूलों को मजबूत करने को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही, हालांकि साथ ही मुख्यमंत्री के फैसलों का सम्मान करने की बात भी स्पष्ट की। इससे सरकार के भीतर नीतिगत फैसलों पर अलग-अलग राय होने की तस्वीर सामने आई है।

दूसरी ओर सरकार के कामकाज को लेकर विभिन्न संगठनों के आंदोलन भी लगातार सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान टैक्सी ऑपरेटरों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अन्य वर्गो की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किये गये हैं। सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा भी कुछ मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर हैं।

कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल अगले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को संभालने का है। सत्ता में होने के बावजूद शिमला जैसे महत्वपूर्ण जिले में जिला परिषद के शीर्ष पद गंवाना पार्टी के लिए सामान्य स्थानीय राजनीतिक घटनाक्रम मानकर टालना आसान नहीं होगा। खासकर तब, जब अगले विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है।

शिमला जिला परिषद का परिणाम कांग्रेस के लिए एक साफ राजनीतिक संदेश है कि सत्ता का प्रभाव तभी चुनावी ताकत में बदलता है, जब संगठन की पकड़ जमीन पर भी दिखाई दे। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकमान दिल्ली में मिले फीडबैक और शिमला के इस परिणाम को किस गंभीरता से लेता है तथा प्रदेश संगठन और सरकार के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए क्या कदम उठाता है।

कर्मचारियों की सेवा चाहिए तो हक भी देना होगा

सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकारों के लिए आईना हिमाचल के वर्षों पुराने कर्मचारी मामलों पर भी उठे सवाल

शिमला/शैल। सरकारी व्यवस्था कर्मचारियों के बिना नहीं चल सकती, लेकिन कर्मचारियों के अधिकारों की बात आते ही सरकारें अक्सर नियमों और तकनीकी पेचीदगियों का सहारा लेने लगती हैं। सुप्रीम कोर्ट का 8 सितंबर 2026 का फैसला इसी रवैये पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम सतनाम सिंह मामले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्षो तक सेवा लेने के बाद कर्मचारी को केवल नियुक्ति की तारीख के आधार पर पेंशन जैसे अधिकार से वंचित करना उचित नहीं माना जा सकता।

यह फैसला हिमाचल सरकार के लिए भी कर्मचारी नीति पर गंभीरता से सोचने का अवसर है। प्रदेश में लंबे समय तक अनुबंध, दैनिक वेतन, एडहॉक और दूसरी अस्थायी व्यवस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का मुद्दा पुराना है। कई कर्मचारियों ने वर्षो तक सरकारी विभागों में सेवाएं दीं, लेकिन उनकी पुरानी सेवा को नियमित सेवा से अलग मानने के कारण उन्हें कई तरह के लाभों को लेकर संघर्ष करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे मामलों को नए नजरिये से देखने की जरूरत सामने लाता है।

सवाल सीधा है कि जब कर्मचारी की मेहनत सरकारी थी तो उसकी सेवा का हिसाब भी सरकारी क्यों नहीं होना चाहिए? जिस कर्मचारी ने वर्षो तक विभाग का काम संभाला, दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं दीं और सरकारी व्यवस्था को चलाने में योगदान दिया, उसके योगदान को केवल नियुक्ति की श्रेणी के आधार पर कमतर कैसे माना जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कर्मचारी की सेवा का वास्तविक स्वरूप देखा जाना चाहिए। केवल नियुक्ति पत्र में लिखे शब्दों को अंतिम आधार नहीं बनाया जा सकता। संबंधित मामले में अदालत ने कर्मचारियों की वास्तविक सेवा और बाद में हुई नियुक्ति की प्रकृति को देखते हुए उनके अधिकारों पर विचार किया।

यही बिंदु सरकार की कर्मचारी नीति के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अस्थायी नियुक्ति सरकार के लिए भले ही प्रशासनिक जरूरत पूरी करने का रास्ता हो, लेकिन कर्मचारी के लिए यह वर्षो की अनिश्चितता होती है। नियमितीकरण में देरी, पुरानी सेवा की गणना को लेकर विवाद और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को लेकर असमंजस कर्मचारी और उसके परिवार के भविष्य पर सीधा असर डालता है।

पेंशन को लेकर भी शीर्ष अदालत की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी के लिए पेंशन केवल कोई सरकारी कृपा या इनाम नहीं है। यह उसकी वर्षो की सेवा से जुड़ा सामाजिक और आर्थिक अधिकार है। ऐसे में केवल तकनीकी आधार पर किसी कर्मचारी को उसके सेवा लाभ से वंचित करना न्याय की कसौटी पर कितना उचित है, यह सवाल अब सरकारों को भी गंभीरता से देखना होगा।

हिमाचल में वर्षो पुराने कर्मचारी मामलों को भी इसी दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। सरकार को यह तय करना होगा कि अस्थायी नियुक्तियों की व्यवस्था को अनिश्चितकाल तक चलाना उसकी नीति नहीं बन सकती। यदि किसी कर्मचारी से वर्षो तक नियमित कर्मचारी की तरह काम लिया गया है तो उसकी सेवा, अधिकार और भविष्य को लेकर भी स्पष्ट नीति होनी चाहिए।

सरकारें कर्मचारियों से पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी की अपेक्षा करती हैं। बदले में कर्मचारियों को केवल वेतन नहीं, बल्कि सेवा की सुरक्षा, सम्मान और उनके वैधानिक अधिकार भी मिलने चाहिए। कर्मचारी की सेवा जब सरकार के लिए महत्वपूर्ण है तो उसके अधिकार भी सरकार की प्राथमिकता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी बुनियादी सवाल को सरकारों के सामने रखता है।

राज्यपाल ने श्री पेजावर मठ के कार्यों की सराहना की

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने नई दिल्ली के वसंत कुंज स्थित श्री पेजावर मठ का दौरा किया। यह मठ उडुपी मठ की एक इकाई है। इस दौरान उन्होंने श्री पेजावर अधोक्षज मठ, उडुपी के 33वें पीठाधिपति श्री श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ स्वामीजी से मुलाकात की। मठ पहुंचने पर गुरुकुल के विद्यार्थियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राज्यपाल का स्वागत किया।

स्वामीजी ने राज्यपाल को मठ की ओर से शिक्षा, आध्यात्मिकता, सामाजिक सेवा और सामुदायिक कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वसंत कुंज में गुरुकुल चलाया जा रहा है, जहां विद्यार्थियों को भारतीय परंपरा और मूल्यों पर आधारित शिक्षा दी जाती है।

राज्यपाल ने मठ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुकुल परंपरा में शिक्षा के साथ अनुशासन, चरित्र निर्माण, सेवा और समाज के प्रति सम्मान को महत्व दिया जाता है।

कविन्द्र गुप्ता ने युवाओं को भारतीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी और सामाजिक माहौल में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना जरूरी है। उन्होंने मठ से प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए आशीर्वाद की कामना भी की।

राज्यपाल ने मां ज्वालामुखी मंदिर में माथा टेका

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध मां ज्वालामुखी मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया।

राज्यपाल ने मंदिर में पूजा-अर्चना की तथा हिमाचल प्रदेश और राष्ट्र के लोगों की समृद्धि एवं कल्याण की प्रार्थना की।

उन्होंने कहा कि हिमाचल के पवित्र मंदिर और तीर्थ स्थल केवल आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र ही नहीं हैं बल्कि प्रदेश की समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा भी हैं। उन्होंने प्रदेश की धार्मिक परंपराओं, प्राचीन विरासत और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यपाल ने मंदिर में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की तथा श्रद्धालुओं और प्रदेश की जनता को अपनी शुभकामनाएं दीं।

आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने दिए सफलता के मंत्र

शिमला/शैल। राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने सोलन के बद्दी स्थित आईसीएफएआई विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए 402 स्नातक विद्यार्थियों को बधाई दी और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि डिग्री हासिल करना शिक्षा का अंत नहीं, बल्कि जीवन के नए चरण की शुरुआत है।

राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को ईमानदारी, अनुशासन, ज्ञान, चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल कर नौकरी प्राप्त करना नहीं, बल्कि युवाओं को अवसर और समस्याओं के समाधान पैदा करने वाला बनाना होना चाहिए।

उन्होंने विकसित भारत-2047 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को ज्ञान, कौशल, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए। एआई और डिजिटल तकनीक के तेजी से विस्तार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता के साथ रचनात्मक सोच, संवेदनशीलता, सहानुभूति और नैतिक मूल्य भी जरूरी हैं।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अपने ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग समाज और राष्ट्र के हित में करने का आहवान किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, नशामुक्त समाज और सामाजिक समरसता के लिए योगदान देने की अपील की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया। कुलाधिपति प्रो. बी. एन. राज और कुलपति प्रो. केशव शर्मा ने उनका स्वागत किया। समारोह में विधायक राम कुमार चौधरी, उपायुक्त मनमोहन शर्मा, पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।

डीसीए को नियामक उत्कृष्टता के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन (डीसीए) को फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) की ओर से नियामक उत्कृष्टता, उद्योग सुविधा और निर्यात संवर्धन के लिए एग्रिशिएशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित आईपीएचईएक्स-2026 के दौरान प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इस उपलब्धि के लिए डीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सम्मान प्रदेश में मजबूत नियामक व्यवस्था, कारोबार में सुगमता और गुणवत्तापूर्ण एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फार्मास्यूटिकल क्षेत्र विकसित करने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने दवा उद्योग में गुणवत्ता और नैतिक मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान हिमाचल को देश और वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने वाले विश्वसनीय फार्मास्यूटिकल हब के रूप में और मजबूत करता है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि यह सम्मान प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने दवा नियमन को प्रभावी बनाने और उद्योग के विकास को सुविधाजनक बनाने में डीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की।

स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने सम्मान को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए इसका श्रेय डीसीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, समर्पण और व्यावसायिक दक्षता को दिया।

कृषि विश्वविद्यालय ने 80 अनुसूचित जाति किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया

शिमला/शैल। चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर के जैविक कृषि एवं प्राकृतिक खेती विभाग ने कांगड़ा जिले के अनुसूचित जाति किसानों के लिए 9 और 10 सितंबर को जैविक खेती पर दो एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें भुआणा, तरेहल और फरेड़ पंचायतों के विभिन्न गांवों के 80 किसानों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत आयोजित प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती की वैज्ञानिक तकनीकों से अवगत कराना तथा इसे टिकाऊ और लाभकारी कृषि पति के रूप में बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम की अध्यक्षता निदेशक प्रसार शिक्षा डॉ. जनार्दन सिंह ने की। उन्होंने किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए मौसमी दलहनी फसलों को अंतरवर्तीय फसल के रूप में उगाने की सलाह दी।

उन्होंने रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवारनाशकों के असंतुलित उपयोग से होने वाले नुकसान के प्रति भी किसानों को जागरूक किया। प्रशिक्षण में डॉ. रामेश्वर, डॉ. गोपाल कतना और डॉ. राकेश ने जैविक खेती, बीज उत्पादन तथा कीट-व्याधि प्रबंधन की जानकारी दी।

किसानों को विश्वविद्यालय के जैविक कृषि फार्म का भ्रमण करवाकर कम्पोस्ट, जैव उर्वरक और जैव-एजेंट तैयार करने की व्यावहारिक जानकारी दी गई। कीट प्रबंधन के लिए किसानों को कृषि उपकरण भी वितरित किए गए। प्रशिक्षण का उद्देश्य किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाने के साथ जैविक खेती को स्थायी रूप से बढ़ावा देना रहा।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

आईआईआईटी ऊना के 29 छात्रों का इन्फोसिस में चयन

शिमला/शैल। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना के वर्ष 2027 में स्नातक होने वाले बैच के 29 छात्रों का इन्फोसिस में पूर्णकालिक रोजगार के लिए चयन हुआ है। चयनित छात्रों को डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर (डीएसई0, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर (एसपी)-एल। और एसपी-एल2 जैसे पदों पर अवसर मिला है।

चयनित छात्र कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसई), इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) शाखाओं से हैं। इनमें से आठ छात्रों ने इन्फोसिस की प्रतिष्ठित 'हैकविथइन्फी' हायरिंग प्रक्रिया के माध्यम से सफलता हासिल की, जबकि 21 छात्रों का चयन कैंपस भर्ती प्रक्रिया के जरिए हुआ।

संस्थान के अनुसार, यह उपलब्धि छात्रों की तकनीकी क्षमता, कोडिंग कौशल, समस्या समाधान क्षमता और उद्योग के अनुरूप तैयारी को दर्शाती है। आईआईआईटी ऊना के निदेशक प्रो. मनीष गौड़ के मार्गदर्शन तथा करियर डेवलपमेंट सेल (सीडीसी) के प्रयासों को इस सफलता में महत्वपूर्ण बताया गया है।

संस्थान ने डॉ. नमन गर्ग और सीडीसी टीम के साथ-साथ संकाय सदस्यों और अन्य सहयोगियों के योगदान की सराहना की।

केंद्र अतिरिक्त वित्तीय मदद के साथ उधार सीमा 4 फीसदी करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर हिमाचल की वित्तीय स्थिति और राज्य की जरूरतों पर चर्चा की। उन्होंने केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के साथ राज्य की उधार सीमा को 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वर्ष 2026-27 से राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के कारण हिमाचल को करीब 8,000 करोड़ रुपये के वार्षिक वित्तीय अंतर का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां आधारभूत

ढांचे के निर्माण और रखरखाव की लागत अधिक है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान ने भी राज्य के वित्तीय दबाव को बढ़ाया है।

मुख्यमंत्री ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत आपूर्ति और विक्रेता भुगतानों को एसएनए-स्पर्श मॉडल से छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत हिमाचल को मिलने वाली सहायता को उसकी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और अधिक निर्माण लागत को देखते हुए दोगुना करने का भी अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि उधार सीमा बढ़ने से राज्य को अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों के साथ जरूरी सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और हिमाचल प्राकृतिक खेती से उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य बना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की वित्तीय जरूरतों और विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सहयोग तथा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता पर विचार किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत सहित प्रदेश और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

एनएलयू के बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू), शिमला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में सहयोग करेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्राओं और छात्रों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण में सरकार मदद करेगी। छात्राओं के छात्रावास की सुरक्षा के लिए कंटीले तारों की बाड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए। परिसर में कम वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए नया ट्रांसफार्मर लगाने तथा छात्रावास के ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली लाइन को हटाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने परिसर के अंदर बिजली की ओवरहेड तारों को भूमिगत करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही जल शक्ति विभाग को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उचित स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। पेयजल की समस्या दूर करने के लिए भी सरकार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय को अपने संसाधन स्वयं बढ़ाने पर भी जोर दिया। एनएलयू की कुलपति प्रो. प्रीति सक्सेना ने विश्वविद्यालय की लंबित समस्याओं पर ध्यान देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बैठक में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जापान के साथ तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाएगा हिमाचल

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जापान के विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएं तलाश रहा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीक और शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने जापान के टोक्यो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान शैक्षणिक सहयोग, अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान और विद्यार्थियों के लिए एक्सपोजर कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। जापान गए इंजीनियरिंग विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार में हिस्सा लेकर वहां की शिक्षा व्यवस्था, अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों की जानकारी हासिल की।

राजेश धर्माणी ने कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय भ्रमण विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के युवा और जापान की तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर भविष्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा कर सकते हैं।

उन्होंने जापान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया और विज्ञान, तकनीक, सतत विकास तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कृषि, बागवानी, जल संसाधनों और प्राकृतिक संपदा को देखते हुए ऐसी तकनीक अपनाने की जरूरत है, जिससे विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण भी हो।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और आधुनिक कौशल उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधान सचिव तकनीकी शिक्षा डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि जापान की नई तकनीकों को समझने में यह भ्रमण विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है।

नशा तस्करों की कमाई पर सरकार का शिकंजा, 29.95 करोड़ की संपत्ति जब्त

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ सरकार ने अब गिरफ्तारी के साथ उनकी आर्थिक ताकत पर भी प्रहार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपये कमाकर बनाई गई संपत्ति का तस्करों को हिसाब देना होगा और ऐसी अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने नूरपुर पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि हाल में करीब 3.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें आलीशान कोठी, जमीन, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं। पुलिस जिला नूरपुर में अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।

सुक्खू ने कहा कि नशे की कमाई उन परिवारों की कीमत पर अर्जित होती है, जिनके बच्चे इस जाल में फंसते हैं। इसलिए सरकार की कार्रवाई केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे नेटवर्क और उसकी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर तक नशा माफिया की मैपिंग की गई है और नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। पीआईटी-एनडीपीएस कानून के तहत आदतन अपराधियों पर भी कठोर कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को नशे का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने जनता से नशा तस्करी से जुड़ी जानकारी पुलिस को देने की अपील की।

पूर्ण साक्षरता उपलब्धि पर हिमाचल को राष्ट्रीय सम्मान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया गया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया।

रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल ने 99.55 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल की है और गोवा के बाद देश का दूसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य बन गया है।

उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग, शिक्षकों, स्वयंसेवकों और आम लोगों के सामूहिक प्रयासों को दिया।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार का यूएलएलएएस कार्यक्रम हिमाचल में वर्ष 2023-24 से लागू किया गया और इसके तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों को शामिल किया गया। यूएलएलएएस पोर्टल पर 94,930 शिक्षार्थियों का पंजीकरण हुआ, जबकि 19,232 स्वयंसेवी शिक्षकों का पंजीकरण और प्रशिक्षण पूरा किया गया।

प्रदेश में तीन एफएलएनएटी परीक्षाओं के माध्यम से 61,542 शिक्षार्थियों का आकलन किया गया, जिनमें 59,896 सफल रहे। इस तरह सफलता दर 97.3 प्रतिशत रही।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भी हिमाचल ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पीजीआई 2.0 में प्रदेश 13वें स्थान से सात पायदान ऊपर उठकर देश में छठे स्थान पर पहुंचा है। वहीं, एनएएस/परख आकलन में सीखने के परिणामों के मामले में हिमाचल पांचवें स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2021 में वह 21वें स्थान पर था।

उन्होंने कहा कि अब सरकार का लक्ष्य साक्षरता को बनाए रखने के साथ आजीवन सीखने, डिजिटल साक्षरता और व्यावसायिक कौशल को बढ़ावा देना है। वर्ष 2026-27 में प्रदेश को 100 प्रतिशत साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने इस उपलब्धि में योगदान देने वाले सभी शिक्षकों, स्वयंसेवकों, शिक्षार्थियों और अधिकारियों का आभार जताया।

सिरमौर की दवा इकाई के खिलाफ डीसीए की कड़ी कारवाई

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश ड्रग्स कंट्रोल प्रशासन (डीसीए) ने सिरमौर के कालाअंब स्थित दवा कंपनी मैसर्स वेलक्योर रेमेडीज के खिलाफ कड़ी नियामक कारवाई की है। यह कारवाई राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में गंभीर कमियां पाए जाने के बाद की गई।

स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पहले बताई गई कुछ कमियां अभी भी दूर नहीं की गई थीं। इसके बाद कंपनी को इन कमियों को पूरी तरह दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मामले में सरकार किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और नियमों का उल्लंघन करने वाली दवा इकाइयों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कारवाई जारी रहेगी।

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कंपनी ने निरीक्षण में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए समय मांगा था। हालांकि, मरीजों की सुरक्षा को देखते हुए कंपनी को फिलहाल उत्पादन शुरू न करने के आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कंपनी सभी कमियों को संतोषजनक तरीके से दूर नहीं करती और नियामक अधिकारियों की संयुक्त टीम इसका सत्यापन नहीं कर लेती, तब तक उत्पादन की अनुमति नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

ब्रिक्स में भारत का शक्ति प्रदर्शन अब घोषणाओं से आगे बढ़ना जरूरी

ब्रिक्स सम्मेलन ने एक बात साफ कर दी है कि दुनिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। कभी अंतरराष्ट्रीय फैसलों पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब चीन, रूस, भारत और दूसरे देशों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। इस बदलती तस्वीर में भारत की स्थिति सबसे अहम है। भारत न तो किसी एक देश के दबाव में है और न ही किसी एक खेमे का हिस्सा बनना चाहता है।

ब्रिक्स का मंच भारत के लिए अपनी ताकत दिखाने का बड़ा मौका है। यहां भारत ने साफ संदेश दिया है कि दुनिया के विकासशील देशों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आतंकवाद, आर्थिक सहयोग, तकनीक, ऊर्जा और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन असली सवाल यह है कि सम्मेलन में हुई बातें जमीन पर कितनी उतरती हैं।

ब्रिक्स में कई ऐसे देश हैं जिनके अपने-अपने हित हैं। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद रहा है। रूस का पश्चिमी देशों के साथ टकराव चल रहा है। पश्चिम एशिया के देशों की अपनी समस्याएं हैं। ऐसे में सभी देशों को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। अगर ब्रिक्स केवल बैठक करने और बयान जारी करने तक सीमित रहा तो इसका कोई बड़ा फायदा नहीं होगा।

भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन को लेकर है। चीन के साथ बातचीत जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता करके नहीं। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन भारत को अपनी सीमा, सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पूरी मजबूती से खड़ा रहना होगा। दोस्ती की बात अपनी जगह है और राष्ट्रीय हित अपनी जगह।

आर्थिक मोर्चे पर भी ब्रिक्स के सामने बड़ी चुनौती है। कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और नई भुगतान व्यवस्था बनाने की चर्चा भी हो रही है। लेकिन केवल डॉलर के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए मजबूत आर्थिक व्यवस्था और देशों के बीच ज्यादा व्यापार जरूरी है।

यहीं भारत के लिए बड़ा मौका है। दुनिया अब चीन पर अपनी जरूरतों के लिए पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। कंपनियां नए देशों में निवेश के रास्ते तलाश रही हैं। भारत के पास बड़ा बाजार, युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। अगर भारत सही नीतियां बनाये तो विनिर्माण, तकनीक, दवा, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में बड़े निवेश हासिल कर सकता है।

लेकिन इसके लिए भारत को सिर्फ सम्मेलन में भाषण देने से आगे बढ़ना होगा। दुनिया में प्रभाव उसी देश का होता है जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जो अपनी जरूरत की चीजें खुद बना सकता है और जिसके पास तकनीक तथा सुरक्षा की ताकत होती है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह अलग-अलग देशों के साथ संबंध रख सकता है। अमेरिका के साथ भी संबंध, रूस के साथ भी बातचीत और चीन के साथ भी संवाद भारत ने यह संतुलन बनाए रखा है। यही भारत की विदेश नीति की खासियत है। लेकिन संतुलन का मतलब यह नहीं कि कोई भी देश भारत पर अपनी शर्तें थोप सके।

ब्रिक्स भारत को दुनिया में अपनी भूमिका और मजबूत करने का अवसर देता है। लेकिन अब समय केवल उपलब्धियां गिनाने का नहीं है। भारत को यह दिखाना होगा कि वह विकासशील देशों की आवाज उठाने के साथ-साथ उनके लिए ठोस काम भी कर सकता है।

ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। अब असली परीक्षा सम्मेलन खत्म होने के बाद है। अगर फैसले जमीन पर उतरते हैं, व्यापार और निवेश बढ़ता है और भारत अपनी आर्थिक व रणनीतिक ताकत को आगे ले जाता है, तभी यह सम्मेलन सफल माना जाएगा। वरना बड़ी-बड़ी बातें और चमकदार तस्वीरें कुछ समय बाद खबरों की भीड़ में खो जाएंगी।

दुनिया बदल रही है। भारत के पास आगे बढ़ने का मौका है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि भारत दुनिया में कितना सुना जा रहा है, सवाल यह है कि भारत अपने हितों के लिए दुनिया में कितना असर पैदा कर सकता है।

आज़ादी केवल अधिकार नहीं, हमें देश के खातिर जिम्मेदारियां भी निभानी होगी

गौतम चौधरी

15 अगस्त बीत चुका है। तिरंगे उतार दिए गए हैं, देशभक्ति के गीतों की आवाज धीमी पड़ गई है और स्वतंत्रता दिवस के मंचों पर दिए गए भाषण अब अगले वर्ष तक स्मृति में रहने वाले हैं। मगर स्वतंत्रता का सवाल 15 अगस्त के साथ समाप्त नहीं होता। असली सवाल तो अब शुरू होता है-जिस आज़ादी का हमने उत्सव मनाया, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी दिखाई देती है?

1947 में भारत ने औपनिवेशिक शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की थी। मगर स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी सत्ता से मुक्ति नहीं है। उसका अर्थ है-हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार, अपने विश्वास और संस्कृति के पालन की स्वतंत्रता, अपनी बात कहने का अवसर, शिक्षा और रोजगार की संभावना तथा देश के निर्माण में बराबरी की भागीदारी।

इसलिए स्वतंत्रता दिवस किसी एक समुदाय का उत्सव नहीं हो सकता। यह हर भारतीय की साझी विरासत है।

भारत की स्वतंत्रता की कहानी भी किसी एक धर्म, जाति या क्षेत्र की कहानी नहीं है। 1857 के संघर्ष से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन तक मुसलमानों सहित विभिन्न समुदायों के लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। बहादुर शाह ज़फ़र, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अनेक ऐसे लोग इस इतिहास का हिस्सा हैं जिनके नाम आज व्यापक रूप से याद नहीं किए जाते। जेल जाने वाले, आर्थिक कठिनाइयां झेलने वाले और पुलिस की कारवाई का सामना करने वाले असंख्य सामान्य भारतीयों ने भी स्वतंत्रता की नींव मजबूत की।

इस इतिहास को याद करने का उद्देश्य किसी समुदाय के योगदान का हिसाब रखना नहीं, बल्कि यह समझना है कि भारत की आज़ादी मूलत: साझे संघर्ष की देन थी। इसलिए आज का भारत भी किसी एक समुदाय की जागीर नहीं हो सकता।

विशेष रूप से भारतीय मुसलमानों के लिए यह समझ महत्वपूर्ण है कि भारतीय होना और अपनी धार्मिक पहचान के प्रति प्रतिबद्ध रहना एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। इसी तरह किसी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध या आदिवासी की सांस्कृतिक पहचान भी उसकी भारतीय नागरिकता को कम नहीं करती। भारत की शक्ति इसी बहुलता में है।

मगर यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि हम दूसरे की गरिमा नष्ट करने को अपना अधिकार समझें। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि दूसरे की आस्था का अपमान किया जाये। राजनीतिक असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, मगर असहमति को दुश्मनी में बदल देना लोकतंत्र को कमजोर करता है।

आज स्वतंत्रता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक डिजिटल दुनिया भी है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दिया है, मगर उसी के साथ झूठ, अफवाह और नफरत फैलाने की गति भी बढ़ी है। शिक्षित नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह किसी सूचना को केवल इसलिए आगे न बढ़ाए कि वह उसकी अपनी धारणा के अनुकूल है। सत्यापन, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण आज नागरिक जिम्मेदारी का अनिवार्य हिस्सा हैं।

यह जिम्मेदारी युवाओं पर सबसे अधिक है। विश्वविद्यालय और कॉलेज केवल डिग्री हासिल करने की जगह नहीं हैं। वे विचार, बहस और लोकतांत्रिक चेतना के निर्माण के केंद्र हैं। आने वाले भारत की दिशा सरकारी नीतियों से जितनी तय होगी, उतनी ही शिक्षित युवाओं की ईमानदारी, प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक संवेदनशीलता से भी तय होगी।

राष्ट्र निर्माण केवल संसद, मंत्रालयों या राजनीतिक दलों का काम नहीं है। ईमानदारी से काम करने वाला शिक्षक, जिम्मेदारी से इलाज करने वाला डॉक्टर, सुरक्षित निर्माण करने वाला इंजीनियर, रोजगार पैदा करने वाला उद्यमी, शोध करने वाला वैज्ञानिक और मेहनत से पढ़ने वाला विद्यार्थी-सब राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं।

इसीलिए 15 अगस्त के बाद हमें अपने भीतर एक दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाने की जरूरत है-आत्ममंथन का स्वतंत्रता दिवस।

क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से लेते हैं? क्या हम कानून का सम्मान करते हैं? क्या हम सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं? क्या हम अपने पड़ोसी की आस्था और अधिकार का सम्मान करते हैं? क्या हम असहमति को सुनने का धैर्य रखते हैं? क्या हम अपने बच्चों को केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी तैयार कर रहे हैं?

स्वतंत्रता की वास्तविक रक्षा इन्हीं सवालों के जवाब में होगी।

तिरंगा साल में एक दिन हमारे हाथ में आता है, मगर भारत की जिम्मेदारी हर दिन हमारे हाथ में रहती है। 15 अगस्त बीत गया है। उत्सव समाप्त हो गया है। अब बारी उस भारत को बनाने की है जिसकी कल्पना स्वातंत्र समर के बलिदानियों व योद्धाओं ने की थी-एक ऐसा भारत जिसमें विविधता विभाजन का कारण नहीं, शक्ति बने, धर्म पहचान हो, संघर्ष का हथियार नहीं, असहमति लोकतंत्र की स्वाभाविक भाषा हो और नागरिकता अधिकार के साथ जिम्मेदारी का भी नाम हो।

आज़ादी हमने विरासत में पाई है। अब उसे अपने आचरण से सार्थक करना हमारी जिम्मेदारी है।

सायर मेले में दिखती है बाघल की सदियों पुरानी लोक परंपरा

डॉ. मस्तराम शर्मा
पूर्व सचिव हिमाचल संस्कृत अकादमी

कुनिहार में अभोज देव 12वीं शताब्दी 1154 के मध्य जम्मू के अखनूर क्षेत्र के एक छोटे से राज्य से आये थे। बाघल की ठाकुरई सतलुज की सहायक गम्भर नदी की घाटी में स्थिति बाघल की स्थापना की गई थी।धारा नगरी से आये पनवर परमार वंशीय युवक अजय देव ने बाघल में 1310 से 1340 तक, और इनके दो भाई विजय देव, मदन देव ने सिरमौर में राज किया।अर्की में बणिया देवी मंदिर, लटरुमुटरु में शिव मंदिर है जिन में भक्ति शिव की आराधना करते हैं। डुगली में राजाओं के महलों के खण्डहर तथा दाडलाघाट के घोघर में भी महलों के अवशेष आज भी मिल जाते हैं। यहां का राजा गूंगा था जो धार्मिक था । बाघल की राजधानी कालीसेल बिलासपुर, शिमला के जतोग तक और कुनिहार से मांगल तक फैली हुई थी। उसके बाद राजधानी धुन्धन बनाई गई । राजा ने अपना निवास स्थान सर डमरास को बनाया गया था । उनके पुत्र नंद देव ने स्वास्थ्य के लिहाज से दाड़ला व धुन्धन में राजधानी बनाई। अजय देव, नून देव, तारा देव से लेकर 36 शासक हुए, जिनमें अन्तिम ध्यान सिंह1876 से 1877 तक, विक्रम सिंह 1904 – 1922, सुरेंद्र सिंह 1922 – 1944, राजेंद्र सिंह 1944 से राज करते रहे। जिसमें इनकी प्रभुता रही। शोभ चंद्र – सभा चन्द्र ने 1640 – 1670 के मध्य 1643 में अर्की को बसाया था, इसे ही अपनी राजधानी बनाया।

हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले की अर्की तहसील एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पृष्ठभूमि वाली महत्वपूर्ण तहसील है यहां उप तहसील दाड़लाघाट भी है। वर्तमान में यहां चार राजकीय महाविद्यालय अर्की , दाड़लाघाट जयनगर हैं। यह क्षेत्र प्राचीनकाल में बाघल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। अर्की तहसील का संपूर्ण भौगोलिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर देखें तो, भूभाग शिवालिक और मध्य हिमालय की पहाड़ियों के बीच स्थित है समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1.0 4 5 मीटर है। इसका क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से 237.9 वर्ग मीटर है। जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शरद ऋतु में ठंडा है। प्रमुख जल स्रोत गम्भर नदी सतलुज की सहायक नदी है। जो उपजाऊ और हरा भरा खेतों को बनती है। यहां कृषि और बागवानी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मक्की, गेहूं, उड़द, रौंगी, कुलथ, टमाटर, अदरक आदि उगाये जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते दाड़लाघाट में विशाल चूना पत्थर के भंडार है जिसके कारण यहां सीमेंट का औद्योगिक प्लांट स्थापित किया हुआ है।अंबुजा सीमेंट अब अदानी समूह मांगल में भी सीमेंट का कारखाना है जिसके कारण स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। पर्यटन की दृष्टि से अर्की में राजवंशीय राजाओं का महल है। महादेव गुफा मंदिर है। जनसंख्या यहां की एकलाख से अधिक हैं। यहां के स्थानीय निवासी लगभग 95% पढ़े – लिखे और विभिन्न विभागों में उच्चपदों पर आसीन है। यहां की भाषा बघलाणी पहाड़ी भाषा है। हिंदी का प्रयोग अधिक होता है। अश्विनी संक्रांति को प्रमुख त्योहार सायर मेला सितंबर मास में लगता है। सायर मेले के दिन बॉवडी, तालाब के किनारे पूजन किया जाता है नई फसल कुक्कड़ी, खीरा ,अखरोट आदि भेंट में चढ़ाए जाते हैं। यहां पर सायर मेले के अवसर पर झोटों की लड़ाई प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। कृषि के संदर्भ में यहां के लोग खेती – बाड़ी करते हैं। जिसमें गेहूं, मक्की, जौ धान, अदरक, प्रमुख फसलों में रहती है। फलों में आड़ू, पलम, खुमानी, अखरोट, नाशपाती आदि होते हैं। राणा पृथ्वी सिंह द्वारा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था। शकनी महादेव मंदिर, रूद्र महादेव मंदिर, लुटुरु महादेव के मंदिर यहां लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लोहार घाट, जयनगर, भूमती दाड़ला घाट आदि यहां के मुख्य स्थान माने जाते हैं। बाड़ी की धार के पूर्व और पश्चिम की और अनेक खड़े हैं, जो बरसात में रूद्र रूप लेकर नदी की भांति अपना प्रभाव बढ़ती है। घनागु घाट का पानी जहां उच्ची धार है एक उत्तर की ओर बरसात का पानी दाती खाद से होते हुए कहलूर की ओर बहता है, जिसमें बाड़ी की धार दातीगांव से जो पश्चिम की ओर है उसका पानी इसी खड से होते हुए दाती वाली खड में मिलकर आगे सतलुज में मिल जाता है। बाड़ी की धार से दूसरी तरफ खाड कुणी का पानी जयनगर बिलासपुर होते हुए सतलुज नदी में समा जाता है। दाड़लाघाट – कराडाघाट चण्ड़ि कशलोग का पानी भी आगे बढ़ते हुए पारनु गांव से आगे बिलासपुर होते हुए सतलुज में समा जाता है। बाघल अर्की क्षेत्र के निवासी धार्मिक दृष्टि से धर्म परायण होते हैं। देवी देवताओं पर पूर्ण विश्वास और सम्मान से आदर करते हैं। ब्राह्मण जहां अपने यजमानों के घर पूजा पाठ करते हैं। वहां देवताओं की पूजा भी घर – घर होती है। क्षत्रिय लोग खेती – बाड़ी करते हैं सभी जातियों के लोग एक दूसरे के सुख – दुख में एकत्रित होते है। अर्की क्षेत्र में जहां देवी देवताओं की पूजा पारंपरिक प्रथाओं से की जाती है, वहां प्रत्येक गांव में किसी न किसी देवी देवता का मंदिर अवश्य होता है। बाड़ी की धार में पांच पांडवों की तपस्थली रही है। जहां इन्होंने शिव भगवान की आराधना की वहां शिव को भी स्थापित किया। उन्हें अज्ञातवास के समय में अपना समय यापन करना पड़ा था। इस स्थान को बाड़ादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दाड़लाघाट के कोटला ग्राम में देवगण का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें हर संक्रांति को देवता का बढ़ेरा भंडारा होता है। लोक देवता के आगे अपनी विनती को रखते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। ग्राम बड़ोग में अच्छू की डाबर भी है जहां स्नान करने पर अनेक प्रकार के रोगों का निवारण होता है। इस प्रकार दाड़लाघाट में और कोटला से दूर घनागु घाट में इसका मेला 20 प्रविष्टि को बाडीधार मेले से पूर्व किया जाता है। दाड़लाघाट में बड़ुवाड़ा देवता का मंदिर भी है, इन दोनों देवताओं के रथ एक – एक दो – दो मास के लिए अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए रथ सहित निकल जाते हैं और देवताओं के नाम से जात रखी जाती है। करार घाट में भी देव मंडोर का मंदिर है। जिसकी जात दानों घाट में हर साल होती है और एक बड़ा मेला लगता है। दाड़लाघाट में एक शिव मंदिर है जिसमें शिव की पूजा की जाती है स्यार में भी शिव का मंदिर है, जिसमें भक्त लोग श्रद्धा से शिव प्रतिमा पर जल अर्पित करते हैं तथा रुद्री का पाठ भी किया जाता है धुन्धन अर्की आदि क्षेत्रों में भी शिव – शक्ति के मंदिर दोनों पाये जाते हैं। बाघल क्षेत्र में भाद्रपद मास के रक्षाबंधन पूर्णमासी से गुगा महाराज की छड़ी निकलती है जो गुगा नवमी तक लोगों के घर – घर में जाकर मंडलियों द्वारा गुगा गाथा गाई जाती है और रात्रि को छड़ी के साथ घरों में स्थापित कर डेरा रखा जाता है और सारी रात गुगा गाथा गाई जाती है। अन्य त्योहारों में बाघल क्षेत्र में दीपावली, दशहरा, होली, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि त्यौहार भी पारंपरिक प्रथाओं के साथ हर साल मनाये जाते हैं। सभी अर्की निवासियों के लिए सायर मेले की बहुत – बहुत शुभकामनाएं।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं को किया जा रहा सुदृढ़

लोगों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की हो रही समयबद्ध आपूर्ति
खाद्य सुरक्षा एवं किसान हितों को मिली मजबूती

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, कृषि उपज की खरीद, उपभोक्ता सेवाएं तथा विभिन्न विभागों को आवश्यक सामग्री की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बीते 46 वर्षों से निगम द्वारा प्रदेशवासियों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निरंतर आपूर्ति की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से उपभोक्ताओं को चावल, आटा तथा अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश के लगभग 19.42 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक माह सब्सिडी युक्त खाद्य तेल, नमक और दालें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। निगम की 54 गैस एजेंसियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एलपीजी सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा संचालित चार पेट्रोल पंप भी लोगों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

निगम के 47 मेडिकल स्टोर के माध्यम से उपभोक्ताओं को 10.25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट पर दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन दुकानों पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं।

निगम विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने में भी सहयोग कर रहा है। इसके तहत सीमेंट, पाइप, दवाइयां, मिड – डे – मील के लिए खाद्य सामग्री तथा ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा से संबंधित कार्यो के लिए आवश्यक सीमेंट की आपूर्ति की जा रही है।

राज्य सरकार किसानों से कृषि उपज की सीधी खरीद कर रही है। वर्ष 2022 – 23 से किसानों से धान की खरीद की जा रही है। वर्ष 2025 – 26 के दौरान अक्तूबर से दिसंबर तक 21,127 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई।

निगम द्वारा वर्ष 2023 – 24 से किसानों से सीधे गेहूं की खरीद भी की जा रही है। वर्ष 2026 – 27 के दौरान अब तक लगभग 4,567.50 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत कृषि विभाग में पंजीकृत किसानों से वर्ष 2025 – 26 के दौरान 217 मीट्रिक टन मक्की की खरीद की गई। वर्ष 2026 – 27 के दौरान लगभग 267.96 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है।

इस पहल के तहत खरीदी गई मक्की और गेहूं को प्रसंस्कृत कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आकर्षक दरों पर 'हिम मक्की आटा' और 'हिम भोग गेहूं आटा' ब्रांड नाम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। कर्मचारी कल्याण कोष की स्थापना की गई है तथा निगम द्वारा कर्मचारियों को बोनस और एक्स – ग्रेशिया सहायता भी प्रदान की जा रही है।

जन शिकायतों के निवारण के लिए निगम के मुख्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। शिकायतें निर्धारित व्यवस्था के माध्यम से जिसमें ई – मेल complaint@himapurti.com भी शामिल है पर दर्ज करवाई जा सकती हैं।

जन सुरक्षा भी राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। केंद्र सरकार के बुनियादी सुरक्षा निरीक्षण अभियान के तहत प्रदेश की 54 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू स्तर पर एलपीजी सुरक्षा निरीक्षण किए गए हैं।

निर्धारित 2,52,420 उपभोक्ताओं के लक्ष्य के मुकाबले 2,42,027 उपभोक्ताओं (96 प्रतिशत) के एलपीजी कनेक्शनों का घर – घर जाकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपभोक्ताओं को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के संबंध में भी जागरूक किया गया।

निगम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों को ई – ग्रेड गुणवत्ता का राशन, खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं, जिनका मूल्य 10 से 15 करोड़ रुपये है, की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।

कठिन परिस्थितियों के दौरान सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्था महत्वपूर्ण मानवीय भूमिका भी निभाती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रभावित परिवारों को नि:शुल्क राशन और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से किया जा रहा यह कार्य खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के प्रति राज्य सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का जोर:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को प्राथमिकता दे रही है। इसी उद्देश्य से गांवों में सीबीएसई स्कूल खोले जा रहे हैं, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए शहरों का रुख न करना पड़े। मुख्यमंत्री 'नारी तू नारायणी' कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित करने के बाद संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए दूध के खरीद मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। सरकार गाय का दूध 61 रुपये और भैंस का दूध 71 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद रही है। इस वर्ष दूध के समर्थन मूल्य पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अक्तूबर तक तैयार होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से पैदा होने वाली गेहूं, मक्की और हल्दी जैसी फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 150 सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और 30 सितंबर तक इनमें सभी शिक्षकों की नियुक्ति पूरी करने का लक्ष्य है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को विदेशों में एक्सपोजर विजिट भी करवाई जा रही है। प्रदेश में करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से पहला साइंस कॉलेज बनाया जा रहा है। हमीरपुर में एलाइड एंड हेल्थकेयर कॉलेज भी खोला जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बीबीएमबी से हिमाचल के एरियर के लिए प्रयास कर रही है और वर्ष 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस कानून लागू किया गया है और चिट्टे के खिलाफ अभियान का दूसरा चरण 16 सितंबर से ऊना में शुरू होगा।

एईडीपी से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ मिलेगा रोजगार का अनुभव

शिमला/शैल। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से 16 राजकीय महाविद्यालयों में अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) शुरू करने के लिए बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, उत्तरी क्षेत्र (बीओएटी-एनआर), कानपुर के साथ समझौता किया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मौजूदगी में बीओएटी-एनआर के निदेशक विवेक कुमार और 16 महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि एईडीपी का उद्देश्य विद्यार्थियों को डिग्री के साथ उद्योगों में काम करने का व्यावहारिक अनुभव देना है। इससे पढ़ाई और उद्योग की जरूरतों के बीच की दूरी कम होगी तथा युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी कौशल मिलेंगे।

इन कार्यक्रमों में बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई), रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स जैसे पाठयक्रम शामिल हैं। विद्यार्थियों को कम से कम छह महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करनी होगी और उन्हें हर माह न्यूनतम 10,900 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा।

पहले चरण में 16 महाविद्यालयों में तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। बी. कॉम. बीएफएसआई 11, रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट दो और लॉजिस्टिक्स तीन महाविद्यालयों में चलाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में अब तक 685 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद इस तरह के अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री कार्यक्रम शुरू करने वाला तीसरा राज्य है। आने वाले समय में बीए और बीएससी जैसे अन्य पाठयक्रमों में भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के 21 राजकीय महाविद्यालयों में बी.वोक. के तहत रिटेल मैनेजमेंट तथा टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के पाठयक्रम चल रहे हैं। इनके बेहतर परिणाम को देखते हुए इनका विस्तार 25 और महाविद्यालयों तक करने का निर्णय लिया गया है।

सीबीएसई स्कूलों के लिए ड्रेस कोड और भवनों की रंग योजना तय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की बैठक में प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के लिए विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, शिक्षकों के ड्रेस कोड और स्कूल भवनों की रंग योजना को अंतिम रूप दिया गया।

निर्णय के अनुसार सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म हरे रंग की थीम पर आधारित होगी। महिला शिक्षिकाएं हल्के लाइलैक रंग की पोशाक पहनेंगी, जबकि पुरुष शिक्षकों के लिए हल्के नीले रंग की पैंट और शर्ट तय की गई है। स्कूल भवनों को ऑलिव ग्रीन और सैंड बेज रंगों में रंगा जाएगा।

शिक्षकों का ड्रेस कोड साफ-सुथरा, औपचारिक और पेशेवर होगा। ड्यूटी के दौरान शिक्षकों के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को घर के नजदीक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। सीबीएसई स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने तथा विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सरकार ने 80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इन स्कूलों के लिए अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये भी जारी किए जाएंगे।

बैठक में विधायक सुरेश कुमार, चंद्र शेखर और नीरज नैय्यर, शिक्षा सचिव राकेश कंवर, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

आईडीबीआई बैंक ने नौणी विश्वविद्यालय को पांच लाख रुपये का ट्रैक्टर भेंट किया

शिमला/शैल। सामुदायिक विकास और संस्थागत साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आईडीबीआई बैंक की सोलन शाखा ने डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को 5 लाख रुपये का ट्रैक्टर भेंट किया। ट्रैक्टर की चाबियां बैंक प्रतिनिधियों ने गुरुवार को एक समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एच.एस. बावेजा को सौंपीं।

इस अवसर पर निदेशक अनुसंधान डॉ. देविना वैद्य सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह पहल आईडीबीआई बैंक के सीजीएम रवि नारायण पातरा, क्षेत्रीय प्रमुख अशोक कुमार सिंघल और शाखा प्रमुख अनुपम चौहान के नेतृत्व में की गई।

ट्रैक्टर का उपयोग विश्वविद्यालय की कृषि और बागवानी गतिविधियों के साथ विशेष रूप से अनुसंधान फार्मो में विभिन्न कृषि कार्यो के लिए किया जाएगा। इससे फार्मो में कृषि कार्यो की दक्षता बढ़ाने और क्षेत्रीय गतिविधियों को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी।

कुलपति प्रो. एच.एस. बावेजा ने आईडीबीआई बैंक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह ट्रैक्टर विश्वविद्यालय के अनुसंधान फार्मो और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए उपयोगी साबित होगा। उन्होंने संस्थागत सहयोग की इस पहल की सराहना की।

बैंक प्रतिनिधियों ने कहा कि स्थानीय समुदाय और प्रमुख संस्थानों के विकास में सहयोग देना बैंक की प्रतिबता का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल विश्वविद्यालय और बैंक के बीच दीर्घकालीन एवं मजबूत संस्थागत संबंधों को और बढ़ावा देंगी।

हिमाचल की ऐतिहासिक धरोहर अब डिजिटल रूप में होगी सुरक्षित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की सदियों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को डिजिटल माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है। राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित दुर्लभ दस्तावेजों के करीब 17 लाख पृष्ठों का डिजिटलीकरण पहले चरण में पूरा हो गया है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की दस्तावेजी धरोहर लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी और शोधकर्ताओं व आम लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराना आसान होगा।

राज्य अभिलेखागार में वर्ष 1807 से अब तक के 30 हजार से अधिक ऐतिहासिक अभिलेख, दुर्लभ पुस्तकें, गजेटियर, सेटलमेंट रिपोर्ट, पांडुलिपियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित हैं। इनका उपयोग देश-विदेश के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों द्वारा किया जाता है।

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि केंद्र के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ज्ञान भारतम् मिशन के तहत प्रदेश में दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और अभिलेखीकरण भी किया जा रहा है। चिन्हित पांडुलिपियों को डिजिटल स्वरूप देने का काम शिमला स्थित हिमाचल राज्य संग्रहालय के क्लस्टर सेंटर से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल दस्तावेजों को आम लोगों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से डिजिटल आर्काइव्स पोर्टल तैयार किया जाएगा। पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री पूरी तरह सर्चेबल होगी और इसे जल्द शोधकर्ताओं, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण में चिन्हित दुर्लभ पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतियां भी राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित रखी जाएंगी। इससे शोधार्थियों को अपनी जरूरत से जुड़ी ऐतिहासिक सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल हिमाचल की ऐतिहासिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने के साथ शोध और ज्ञान के प्रसार को भी नई गति देगी।

फोरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में हमीरपुर वन सर्कल चैंपियन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने रामपुर में आयोजित हिमाचल प्रदेश वन विभाग की 27वीं वार्षिक खेलकूद एवं कर्तव्य प्रतियोगिता के विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई दी। 11 से 13 सितंबर तक आयोजित तीन दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेशभर से एक हजार से अधिक वन कर्मियों ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के समर्पण, मेहनत, अनुशासन और खेल भावना की सराहना करते हुए कहा कि खेल शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक संतुलन, टीम भावना, नेतृत्व और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर ऐसे आयोजन कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ-साथ आपसी भाईचारा और एकता मजबूत करने का अवसर देते हैं।

उन्होंने कहा कि वन विभाग प्रदेश की वन संपदा और जैव विविधता के संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विभागीय कर्मचारियों के लिए खेल गतिविधियां उन्हें स्वस्थ और सक्रिय रखने में भी सहायक हैं।

प्रतियोगिता में हमीरपुर वन सर्कल ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती, जबकि रामपुर वन सर्कल दूसरे स्थान पर रहा। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए भविष्य में भी खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई।

बक्सर परियोजना की दोनों इकाइयां चालू 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू

शिमला/शैल। एसजेवीएन की बिहार के बक्सर जिले के चौसा में बनी 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई भी शुरू हो गई है। 660 मेगावाट की इस इकाई ने 12 सितंबर 2026 को व्यावसायिक रूप से बिजली उत्पादन शुरू कर दिया। इसके साथ ही परियोजना की दोनों इकाइयां चालू हो गई हैं।

यह एसजेवीएन की पहली ऐसी ताप विद्युत परियोजना है, जिसकी दोनों इकाइयां पूरी तरह चलने लगी हैं। करीब 13,756 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस परियोजना से हर साल करीब 9,828 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इसमें से 85 प्रतिशत बिजली बिहार को दी जाएगी।

एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने इस उपलब्धि पर केंद्र और राज्य सरकारों, संबंधित

विभागों, कर्मचारियों और सभी सहयोगियों का आभार जताया। परियोजना के निर्माण के दौरान करीब 65 हजार श्रमिकों को रोजगार मिला। परियोजना के शुरू होने से बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और पीक समय में बिजली की कमी कम करने में मदद मिलेगी।

हिमाचल के बिजली हितों से जुड़े लंबित मामलों पर केंद्र से जल्द समाधान मांगा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर

हिमाचल प्रदेश के विद्युत क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लंबित मामलों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इन मामलों का जल्द समाधान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल के निःशुल्क विद्युत हिस्से के बदले नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र देने का मामला उठाया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम के निदेशक मंडल में प्रदेश की ओर से दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने का आग्रह किया।

उन्होंने शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल को सौंपने का मुद्दा भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पर राज्य के अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 की जलविद्युत नीति से पहले शुरू केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए परियोजना शुरू होने के बाद एक प्रतिशत अतिरिक्त मुफ्त बिजली देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि इससे परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के विकास में मदद मिलेगी। राज्य के आकलन के अनुसार इससे हिमाचल को करीब 29.34 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ हो सकता है।

उन्होंने 180 मेगावाट बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना को 40 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद हिमाचल को सौंपने की प्रक्रिया जल्द आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने बीबीएमबी के कब्जे वाली ऐसी भूमि, जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, प्रदेश सरकार को उपलब्ध करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल सरकारी कार्यालयों के निर्माण और परियोजनाओं से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलविद्युत क्षेत्र हिमाचल की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय विकास का प्रमुख आधार है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सभी मामलों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पंचायतों में मौसम निगरानी नेटवर्क के लिए केंद्र से मांगा सहयोग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर हिमाचल में विज्ञान एवं

प्रौद्योगिकी से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों तक विज्ञान और आधुनिक तकनीक का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री ने लाहौल-स्पीति और पांगी में लद्दाख के हानले की तर्ज पर खगोलीय केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खगोलीय अनुसंधान और अवलोकन के लिए बेहतर परिस्थितियां हैं। ऐसे केंद्रों से विद्यार्थियों और युवाओं में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और ज्ञान आधारित पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने राज्य में लैवेंडर की खेती को बढ़ावा देने के लिए सीएसआईआर के माध्यम से अधिक डेमोंस्ट्रेशन साइट्स स्थापित करने में सहयोग मांगा। इससे किसानों को खेती की तकनीक समझने और लैवेंडर को वैकल्पिक आय के साधन के रूप में अपनाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने आकांक्षी विकासखंडों के स्कूलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को विज्ञान को व्यावहारिक रूप से समझने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वचालित वर्षामापी और विकासखंड स्तर पर स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने की पहल में तेजी लाने का आग्रह किया। इससे स्थानीय स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी और किसानों को खेती की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बाढ़ प्रभावित नदियों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट नियम मांगे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर हिमाचल के बाढ़ प्रभावित नदी

क्षेत्रों में वैज्ञानिक ड्रेजिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र से ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट और सक्षम दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश, बाढ़ और फ्लैश फ्लड के बाद नदियों में बड़ी मात्रा में मलबा, बोल्डर, पत्थर और रेत जमा हो जाती है। इससे नदियों की पानी ले जाने की क्षमता घटती है और बस्तियों, सड़कों, पुलों तथा अन्य बुनियादी ढांचे पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे क्षेत्रों में समय पर वैज्ञानिक ड्रेजिंग जरूरी है।

उन्होंने वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर ड्रेजिंग प्रस्तावों का समयबद्ध निपटारा करने और पर्यावरण मंत्रालय के परिवेश पोर्टल पर नदी ड्रेजिंग के लिए अलग श्रेणी बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के बाद नदी से मलबा हटाने का उद्देश्य खनन नहीं, बल्कि नदी का प्रवाह सुचारू करना और आपदा का खतरा कम करना है।

मुख्यमंत्री ने ड्रेजिंग कार्यों को क्षतिपूरक वनीकरण की अनिवार्यता से छूट देने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में ड्रेजिंग वैज्ञानिक आकलन, रीप्लेनिशमेंट स्टडी और विस्तृत योजना के आधार पर ही की जाएगी। यह काम गैर-मानसून अवधि में पर्यावरणीय मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए किया जाएगा।

उन्होंने ड्रेजिंग से निकलने वाली सामग्री के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग की व्यवस्था बनाने की जरूरत भी बताई। इससे मिलने वाले शुद्ध राजस्व को सतत विकास और वन गतिविधियों में लगाने का प्रस्ताव रखा गया।

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिमाचल में वैज्ञानिक ड्रेजिंग के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने और आवश्यक प्रक्रियाओं को सुगम बनाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि नदी प्रबंधन और आपदा जोखिम कम करने के लिए हिमाचल की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहयोग दिया जाएगा।

जापान की तकनीकी दक्षता से हिमाचल के युवाओं को जोड़ने की संभावनाएं तलाशेगा प्रदेश

शिमला/शैल। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने जापान के टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में उप-मिशन प्रमुख आर.

मधु सूदन से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश के विद्यार्थियों और युवाओं को जापान की तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के वैश्विक अवसरों से जोड़ने पर विस्तार से चर्चा हुई।

राजेश धर्माणी ने कहा कि जापान की तकनीकी दक्षता, नवाचार और कार्य-पद्धतियों से हिमाचल के युवाओं को जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। इससे युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि एआई और नई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कौशल बढ़ाना समय की आवश्यकता है और जापान इस दिशा में हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी बन सकता है।

बैठक में हिमाचल में प्रस्तावित स्किल अकादमी में जापानी उद्योगों और संस्थानों की भागीदारी की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण तथा जापानी कार्य-पद्धतियों को अपनाने पर विचार-विमर्श किया गया।

धर्माणी ने जापान में हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध एवं आध्यात्मिक विरासत और शांत वातावरण जापानी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। धर्मशाला में दलाई लामा की मौजूदगी ने हिमाचल को वैश्विक आध्यात्मिक पहचान दिलाई है।

आर. मधु सूदन ने भारत-जापान संस्थागत सहयोग बढ़ाने में भारतीय दूतावास की भूमिका की जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बैठक में हुई चर्चा को जापानी संस्थानों के साथ आगे बढ़ाकर कौशल, तकनीक और रोजगार के क्षेत्र में दीर्घकालीन सहयोग स्थापित किया जाएगा।

कांगड़ा एयरपोर्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट दो माह में होगी तैयार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु

राममोहन नायडू से मुलाकात कर हिमाचल में हवाई संपर्क और विमानन सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार का मामला प्राथमिकता से उठाया और बताया कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार की टेक्नो-इकोनॉमिक फीजिबिलिटी रिपोर्ट दो माह के भीतर अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। इसके लिए सक्षम सलाहकार नियुक्त करने और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से परियोजना की लागत का यथार्थ आकलन करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। बेहतर हवाई संपर्क से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित हेलीपोर्ट का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्रों में हवाई संपर्क और आपात सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। केंद्रीय मंत्री ने उड़ान योजना के तहत हिमाचल में हेलीपोर्ट निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमति जताई।

शिमला एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों के संचालन पर भी चर्चा हुई। केंद्र ने नियमित हवाई संपर्क के लिए आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। रनवे की क्षमता के अनुरूप उपयुक्त विमानों के संचालन की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।

मुख्यमंत्री ने कांगड़ा एयरपोर्ट की तर्ज पर शिमला एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था सीआईएसएफ के स्थान पर हिमाचल पुलिस को सौंपने का आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्रालय ने सहमति व्यक्त की।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

कैग के आंकड़ों ने खोली 'व्यवस्था परिवर्तन' की पोल

शिमला/शैल। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन के पटल पर रखी गई कैग की ऑडिट रिपोर्ट ने सुक्खू सरकार के वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था पर विपक्ष को सरकार घेरने का बड़ा मुद्दा दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने

रिपोर्ट को सरकार के कथित 'व्यवस्था परिवर्तन' की पोल खोलने वाला दस्तावेज करार देते हुए कहा कि रिपोर्ट में जिस तरह की अनियमितताएं सामने आयी हैं, उनसे साफ है कि सरकार की व्यवस्था में पारदर्शिता के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी पूरा नकाब नहीं उतरा है, आने वाले समय में सरकार के कामकाज से जुड़े और तथ्य सामने आएंगे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑनलाइन टेंडरिंग से लेकर सरकारी खरीद, टैक्स वसूली और वित्तीय प्रबंधन तक कई स्तरों पर सवाल खड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि सरकार की लापरवाही का सीधा नुकसान प्रदेश के खजाने को हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि यदि सरकारी व्यवस्था इतनी पारदर्शी है तो कैग को बार-बार अनियमितताएं क्यों पकड़नी पड़ीं? इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदारी किसकी है और प्रदेश के राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

नेता प्रतिपक्ष ने सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों की ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही आईपी एड्रेस से बोलियां दाखिल की गईं। कुछ मामलों में विभागीय आईपी एड्रेस के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। बोलियों में बेहद मामूली अंतर होने पर भी सवाल खड़े होते हैं।

जयराम ने सीधे सवाल किया कि विभाग के दफ्तर में बैठकर विभाग के ही कंप्यूटर या इंटरनेट से ई-टेंडर भरने की नौबत कैसे आई? यदि विभागीय संसाधनों से बाहर के लोगों ने टेंडर भरे तो उन्हें इसकी सुविधा किसने दी? और यदि यह सब विभाग के कर्मचारियों की जानकारी में हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर प्रक्रिया में विभाग और कुछ ठेकेदारों के बीच मिलीभगत की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। जयराम ने सरकार से पूछा कि आखिर इन टेंडरों का लाभ किन लोगों को मिला और क्या पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी।

जयराम ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार करीब 438 करोड़ रुपये ऐसे खर्च किए गए जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं था, जबकि करीब 673 करोड़ रुपये की योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए लेकिन खर्च नहीं हुआ।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश पहले ही बढ़ते राजस्व और राजकोषीय घाटे की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में यदि बिना बजट प्रावधान के पैसा खर्च हो रहा है तो सरकार को इसकी पूरी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू ट्रेजरी की नकदी स्थिति है। सरकार के पास रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए भी कई बार पर्याप्त नकदी नहीं थी। साल के 162 दिन यानी करीब हर तीन में से एक दिन सरकारी खजाना तय न्यूनतम नकदी से नीचे रहा। 12 महीनों में ट्रेजरी 42 बार ओवरड्राफ्ट हुई, यानी खाते में उपलब्ध रकम से ज्यादा खर्च चलाने के लिए अस्थायी उधार लेना पड़ा। साल के अंत तक 1,652.42 करोड़ रूपये की ओवरड्राफ्ट राशि बकाया रही और इस उधारी पर 12.40 करोड़ रूपये अतिरिक्त ब्याज देना पड़ा। इसके अलावा सरकार ने आरबीआई से 120 बार वेज़ एंड मीन्स एडवांस लेकर कुल 11,276.83 करोड़ रूपये जुटाए। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार की नकदी की स्थिति ऐसी रही कि उसे बार-बार उधार लेकर सरकारी खर्च चलाना पड़ा।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वित्तीय परेशानी का असर अब विकास योजनाओं पर भी पड़ रहा है। विकास कार्यों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए उपलब्ध धन के इस्तेमाल, उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित रहने और योजनाओं की लागत बढ़ने से कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। उनका कहना था कि समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिलने से अगली किस्तों का आवंटन प्रभावित होता है और कई मामलों में राशि वापस लौटाने की स्थिति बनती है।

जयराम ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया कि अगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो सरकार को बार-बार ओवरड्राफ्ट और वेज़ एंड मीन्स एडवांस का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वर्ष 2027 तक आत्मनिर्भर हिमाचल और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन कैग के आंकड़े प्रदेश की वित्तीय हकीकत कुछ और ही बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने का वास्तविक आर्थिक फार्मूला क्या है।

मनमानी नियुक्तियों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जयराम ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली पर अदालत के फैसलों से भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियुक्तियों में नियमों को दरकिनार कर रहे हैं।

जयराम ने कहा कि एक तरफ सरकार 'व्यवस्था परिवर्तन' का दावा करती है, दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है और अदालत के फैसले सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ता के बल पर मनमानी ज्यादा दिन नहीं चल सकती। सरकार को संविधान, कानून और वित्तीय नियमों के दायरे में रहकर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सरकार के वित्तीय फैसलों का आईना है। अब सरकार को जवाब देना होगा कि प्रदेश के खजाने और सरकारी व्यवस्था का इस्तेमाल किसके हित में हुआ।

डॉक्टरों के एनपीए, एडहॉक प्रमोशन और जॉब ट्रेनी नियुक्तियों पर उठे सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के ट्रांसफर और प्रमोशन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के ट्रांसफर और प्रमोशन के लगातार आदेश जारी हो रहे हैं। लेकिन प्रमोशन के बाद वित्तीय लाभ को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से डॉक्टरों में असमंजस बना हुआ है। उनका कहना है कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि प्रमोशन किस तारीख से प्रभावी होगी और उससे जुड़े आर्थिक लाभ कब से मिलेंगे। मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के पद पर की जा रही प्रमोशन को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें प्रमोशन देकर नई जिम्मेदारी तो दी जा रही है, लेकिन व्यवस्था अभी भी एडहॉक आधार पर चल रही है। उनकी मांग है कि सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन को नियमित किया जाए और प्रमोशन की तारीख से ही उससे जुड़े सभी वित्तीय लाभ दिये जायें।

प्रमोशन और वित्तीय लाभ को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टरों का कहना है कि यदि सरकार समय रहते नीति स्पष्ट कर दे तो ऐसे विवाद अदालत तक जाने से रोके जा सकते हैं।

डॉक्टरों की नाराजगी केवल प्रमोशन तक सीमित नहीं है। एनपीए बंद होने का मुद्दा भी लगातार उठ रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि देश के कई राज्यों में सरकारी डॉक्टरों को नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि हिमाचल में इसे बंद रखा गया है। सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसे में एनपीए उनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ है। डॉक्टरों का कहना है कि एनपीए बंद होने से उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार को इस पर स्पष्ट फैसला लेना चाहिए।

डॉक्टरों की जॉब ट्रेनी के नाम पर की जा रही नियुक्तियों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई और प्रशिक्षण में कई साल लगते हैं। इसके बाद डॉक्टरों को नियमित सेवा देने के बजाये जॉब ट्रेनी के नाम पर नियुक्त करना उनके पेशे के साथ उचित नहीं है।

हालांकि हिमाचल सरकार ने अगस्त माह में जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) का मासिक वेतन 33,660 से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया है। पीजी डॉक्टरों, सीनियर रेजिडेंट और सुपर स्पेशलिस्ट के स्टाइपेंड में भी बढ़ोतरी की है। फिर भी डॉक्टरों का तर्क है कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विभाग में डॉक्टरों को स्पष्ट सेवा शर्तों और नौकरी की सुरक्षा के साथ नियुक्त किया जाना चाहिए। ट्रेनी के नाम पर लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था रखना डॉक्टरों के मनोबल पर असर डाल सकता है।

स्वास्थ्य विभाग पहले ही डॉक्टरों की कमी और दूरदराज के अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने की चुनौती से जूझ रहा है। ऐसे में डॉक्टरों के बीच प्रमोशन, वेतन लाभ, एनपीए और नियुक्ति व्यवस्था को लेकर बढ़ता असंतोष सरकार के लिए चिंता का विषय है।

सरकार को अब इन सभी मामलों पर स्पष्ट नीति बनानी होगी। प्रमोशन सिर्फ कागज पर नहीं होनी चाहिए। उसके साथ पद के अनुसार वित्तीय लाभ भी मिलना चाहिए। एनपीए पर फैसला होना चाहिए और जॉब ट्रेनी के नाम पर नियुक्तियों की व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है तो डॉक्टरों का मनोबल भी मजबूत करना होगा।